

प्रेषकः

प्रदीप रिह रावत
राम सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

रेका मे

मुख्य अभियन्ता स्तर-१
लोक निर्माण विभाग
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-२

देहरादून, दिनांक ० | अक्टूबर, २००८

विषय:- महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष २००८-०९ में धनावंटन।

महोदय,

महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु ₹० ४६१.०० लाख के टी.ए.सी. द्वारा अनुमोदित कार्य के विपरीत वित्तीय वर्ष २००५-०६ में शासनादेश संख्या-८२८ / १११(२) / ०६-४९(प्रा०आ०) / ०४, दिनांक २८.०३.०६ के द्वारा ₹०१.०० लाख तथा वित्तीय वर्ष २००६-०७ में शासनादेश संख्या २६४६ / १११(२) / ०६-४९ (प्रा०आ०) / ०४, दिनांक १२.०९.२००६ के द्वारा ₹० ४५१.०० लाख की धनराशि अवमुक्त कर आपके निर्वतन पर रखते हुये सम्पूर्ण धनराशि के व्यय की अनुमति प्रदान की गयी थी। इसी कम में आपके पत्र संख्या-१३२८ / ४२बजट(राज्य सम्पत्ति कार्य -आयोजनेतर) / ०७-०८, दिनांक ०४.०६.२००७ द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष ₹० ५१.०० लाख का उपयोग किया गया है।

इस सबंध में आपके पत्र दि० ०४.०६.२००७ तथा उपरिउल्लिखित शासनादेशों के कम में शासनादेश सं०-१८५८ / १११-२ / ०७-४९(प्रा०आ०) / २००४ दिनांक १० अगस्त, २००७ के द्वारा जनपद देहरादून में महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत ₹० ४६१.०० (₹० चार करोड़ इक्सठ लाख मात्र) के विरुद्ध अवशेष धनराशि ₹० ४१०.०० लाख (₹० चार करोड़ दस लाख मात्र) की धनराशि वित्तीय वर्ष २००७-०८ में व्यय किये जाने की अनुमति प्रदान की गई थी।

वित्तीय वर्ष २००७-०८ में अवमुक्त धनराशि ₹० ४१०.०० लाख के सापेक्ष ₹० २१०.०० लाख ही व्यय किये जाने पर अवशेष धनराशि ₹० २००.०० लाख का समर्पण आपके पत्र सं०-१००२२ / २३ बजट(वा०वि०आ०-भवन कार्य) / २००७-०८ दिनांक ३१.३.२००८ के द्वारा किये जाने से अवगत कराया गया है। तत्पश्चात् निर्माण कार्य की अच्छी प्रगति को दृष्टिगत रखते हुए अवशेष धनराशि ₹० २००.०० लाख अवमुक्त किये जाने संबंधी आपके पत्र सं०-२५७२ / २३ बजट(वा०वि०आ०-भवन कार्य) / २००८-०९ दिनांक ९.७.२००८ के रांदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में महामहिम श्री राज्यपाल आवास के निर्माण हेतु अनुमोदित लागत ₹० ४६१.०० (₹० चार करोड़ इक्सठ लाख मात्र) के विरुद्ध अवशेष धनराशि ₹० २००.०० लाख (₹० दो करोड़ मात्र) की धनराशि की वित्तीय वर्ष २००८-०९ में व्यय किये जाने की अनुमति श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।-

२- स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग दिनांक ३१.०३.२००९ तक किया जायेगा तथा धनराशि का उपयोग निश्चित समय सीमा के अन्तर्गत न करने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता का पूर्ण उत्तरदायित्व होगा। कोई धनराशि यदि दिनांक ३१-०३-०८ तक अवशेष रहती है तो इसका समर्पण विगत वर्षों की भाति न कर समयान्तर्गत विभागाध्यक्ष के माध्यम से ही शासन को किया जायेगा। ऐसा न करने पर इसे गम्भीरता से लिया जायेगा और संबंधित अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी। धनराशि स्वीकृत होने के बाद समय से समर्पित/उपयोग करने का दायित्व भी इस हेतु उत्तरदायी अधिकारी का ही बनता है।

३- निर्माण कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाय।

4— शेष शर्त शासनादेश संख्या-828 / 111(2) / 06-49(प्रा.आ.) / 04 दिनांक 28.03.06 एवं शासनादेश संख्या 2646 / 111(2) / 06-49 (प्रा.आ.) / 04, दिनांक 12.09.2006, शासनादेश सं-1858 / 111(2) / 07-49(प्रा.आ.10) 2004 दिनांक 10 अगस्त 2007 एवं शासनादेश सं-1858 / 111-2 / 07-49(प्रा.आ.10) / 2004 दिनांक 10 अगस्त, 2007 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार गथावत रहेंगी।

5— उक्त निर्माण कार्य अनुमोदित लागत रु0 461.00 लाख की सीमा के अन्दर पूर्ण किया जाय तथा इस सबध में पुनरीक्षित आगणन स्वीकार नहीं किया जाय।

6— इस सबध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2008-2009 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-07 लेखाशीषक-4059 लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-80 सामान्य-आयोजनागत-800-अन्य भवन-01 केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनाये-01-12 वें वित्त आयोग के अन्तर्गत राज्य अवस्थापना विकास-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

7. यह आदेश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-यूओ- 717/XXVII(2)/2008 दिनांक 25 सितम्बर, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

महाराजा
(प्रदीप सिंह राघव)
उप सचिव

संख्या-3233 (1) / 111 (2) / 08-49(प्रा.आ.10) / 2004, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित -

- 1— मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2— महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओवरोन्य मोटर्स विलिंग, माजरा देहरादून।
- 3— निदेशक, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, काइनेन्स कमीशन डिविजन, 11 ब्लाक 5वीं ताल, सी जी ओ काम्पलेक्स, लौधी रोड नई दिल्ली।
- 4— सचिव, श्री राज्यपाल उत्तराखण्ड।
- 5— आयुक्त यदवाल मडल, पांडी।
- 6— अपर सचिव वित्त (बजट) अनुभाग उत्तराखण्ड।
- 7— जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 8— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 9— मुख्य अभियन्ता, गढवाल क्षेत्र, लो०नी०वि०, पांडी।
- 10— अधीक्षण अभियन्ता नवा वृत्त लो०नी०वि० देहरादून।
- 11— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड शासन।
- 12— वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रक्रोष्ट उत्तराखण्ड शासन
- 13—लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन/गाड बुक।

आज्ञा से,
माझा
(महिंगा)
अनु सचिव